Central Water Commission
WSE Dte.,
****

West Block II, Wing No-4
R. K. Puram, New Delhi – 66.

Dated 09.05.2019

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings will be uploaded on the CWC website.

Sanjan
9/5/2019
Senior Artist
WSE, Dte.,

Encl: As stated above.

9/C

Deputy Director, WSE Dte. On leave.

Director, WSE Dte.

9/5

For information to

Chairman CWC, New Delhi

Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Jansatta, Delhi
Thursday, 9th May 2019

जल प्रबंधन की चुनौती

सुविज्ञा जैन

असमान बारिश और लचर जल प्रबंधन की वजह से भारत में साल दर साल अपनी जरूरत की तुलना में पानी कम पड़ने लगा है। आलम यह है कि इस समय भारत की साठ करोड़ आबादी पानी के मामले में अति-अभाव से लेकर गंभीर अभाव वाली स्थिति में बताई जाती है। हर साल करीब दो लाख लोग साफ पानी तक पहुंच न होने से काल के गाल में समा रहे हैं।

जल संकट हर साल गहराता जा रहा है। इस साल गर्मियां आते ही महाराष्ट्र और गुजरात से खबरें आने लगीं कि वहां के बांधों में जमा पानी काफी कम बचा है। यानी बारिश आने में बचे पांच हफ्तों में जल संकट का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग हर हफ्ते बिना नागा देश के बांधों में बचे पानी का हिसाब बताता है। अब यह अलग बात है कि देश में बने पांच हजार बांध हमारी जरूरत जितना पानी रोक कर नहीं रख पाते। बढ़ती जरूरत के मुताबिक देश में जल भंडारण की क्षमता बढ़ नहीं पाई है। दरअसल, अरब घन मीटर की इकाई में पानी के आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन जल प्रबंधकों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि देश में रोजाना पानी की मांग तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अगर बढ़ती जरूरतों का हिसाब लगा कर नहीं रखा गया तो किसी भी वक्त बड़े जल संकट की खबर सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

हमें यह भी जान लेना चाहिए कि केंद्रीय जल आयोग के हफ्तेवार आंकड़े हैं किस काम के? हर हफ्ते देश के बांधों में बचे पानी की मात्रा से हमें जानकारी क्या मिलती है? जल आयोग की दी नवीनतम जानकारी यह है कि देश के बांधों में मई के पहले हफ्ते में लगभग उतना पानी जमा है जितना पिछले साल था। साथ ही यह भी बताया गया है कि पिछले दस साल में बांधों में जितना पानी औसतन रहता आया है उतना पानी इस साल भी है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात अपवाद हैं। वहां के जल संकट की गंभीरता इसलिए छुप गई कि इनक्यानवे बांधों में जल भंडारण के आंकड़ों को जोड़ कर और फिर भाग देकर जो आंकड़ा बना वह हालात को सामान्य बताता है। यह भी गौरतलब है कि यह आंकड़ा देश के सिर्फ इनक्यानवे बांधों की निगरानी से ही निकाला जाता है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता सिर्फ एक सौ बासठ अरब घनमीटर है। जबकि देश में कुल बांधों की संख्या पांच हजार के लगभग है। हालांकि तब भी सबकी भंडारण क्षमता मिला कर भी दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर ही है।

इनक्यानवे प्रमुख बांधों को देश के पांच क्षेत्रों में बांटा जाता है। नई रिपोर्ट के मुताबिक चिंता पश्चिमी क्षेत्र के सत्ताईस बांधों में जल स्तर को लेकर है। इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। इस क्षेत्र के बांधों की कुल क्षमता 31.26 अरब घनमीटर है। जबकि दो मई के बुलेटिन के मुताबिक इस समय उपलब्ध जल भंडारण सिर्फ 5.22 अरब घनमीटर है। बचे पानी का आंकड़ा वहां के बांधों की कुल क्षमता का सत्रह फीसद है, जबकि पिछले साल इसी हफ्ते में यह तेईस फीसद था। अगर दस साल का औसत देखें तो इन बांधों में इस समय तक औसतन छब्बीस फीसद पानी बचा रहता था। जल प्रबंधक यह अच्छी तरह समझते हैं कि जहां इन दिनों औसतन छब्बीस फीसद पानी रहता हो, वहां इस साल उन्हीं दिनों अगर यह स्तर सिर्फ सत्रह फीसद हो तो आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में क्या हालत बन सकती है।

मसला सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात का नहीं माना जाना चाहिए। यह तथ्य कम चिंताजनक नहीं है कि पिछले कई साल से हमारी जल भंडारण क्षमता कमोबेश जस की तस है। पिछले एक दशक से यह क्षमता दो सौ पचास अरब घनमीटर के आसपास ही बनी हुई है, जबकि इस दौरान आबादी चौदह से पंद्रह करोड़ बढ़ गई। गौरतलब है कि प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की जरूरत का आंकड़ा दो हजार घनमीटर है। यानी बढ़ती आबादी के हिसाब से कल कारखाने, बिजलीघर चलाने और अनाज उगाने के लिए पानी की जरूरत बढ़ती गई। यानी केंद्रीय जल आयोग के ये आंकड़े अगर यह कहते हों कि देश के बांधों में उपलब्ध पानी सामान्य मात्रा में है तो यह बात कच्ची और अधूरी क्यों नहीं समझी जानी चाहिए।

अब जब यह अंदेशा खड़ा हो गया है कि अल नीनो प्रभाव के कारण इस साल पानी कम गिरने का अंदेशा है तो संकट की नई घंटी बजती दिख रही है। इतना ही नहीं, इस साल पृथ्वी दिवस पर जताई गई जलवायु परिवर्तन की चिंता खतरे की दूसरी घंटी है। इसीलिए बढ़ते वैश्विक तापमान को पानी की उपलब्धता के नजरिए से भी देखने की जरूरत है। शोध अध्ययनों में निकल कर आ रहा है कि

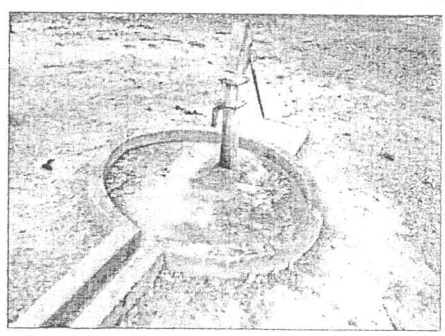

आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। सन 1880 से लेकर 2003 तक के आंकड़ों से पता चला था कि पृथ्वी औसतन हर दस साल में 0.05 डिग्री सेल्सियस यानी एक डिग्री सेल्सियस के बीसवें हिस्से की रफ्तार से गर्म हुई। लेकिन सिर्फ 1975 से लेकर 2003 तक के अंतराल में पृथ्वी के गरम होने की रफ्तार प्रति दस साल 0.22 डिग्री सेल्सियस हो गई। पहले की तुलना में यह रफ्तार साढ़े चार गुनी बढ़ गई। इस लिहाज से पचास साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। पर्यावरण विज्ञानियों के मुताबिक यह एक ऐसा बदलाव है जो जीव जगत के लिए खतरे की घंटी तो है ही, उसके साथ-साथ जलचक्र में बदलाव की चेतावनी भी है।

जलवायु संकट से वर्षा चक्र गड़बड़ा रहा है। वर्षा अवधि पर असर पड़ रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में वर्षा की असमानता बढ़ती जा रही है। जब तापमान बढ़ता है तो ज्यादा पानी भाप बन कर उड़ता है। समुद्री इलाके में अचानक दाब परिवर्तन होने से चक्रवात और तूफान पैदा होते हैं। तूफानों से कई इलाकों में अचानक ज्यादा पानी बरस जाता है जिससे बाढ़ और दूसरी तबाहियां झेलनी पड़ती हैं। जहां कम बारिश होती है उन क्षेत्रों को सूखे और पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है।

वैसे तो आजकल आपूर्ति के मामले में पूरे विश्व में जल संकट है, लेकिन भारत के लिए यह मुश्किल ज्यादा बड़ी है। असमान बारिश और लचर जल प्रबंधन की वजह से भारत में साल दर साल अपनी जरूरत की तुलना में पानी कम पड़ने लगा है। आलम यह है कि इस समय भारत की साठ करोड़ आबादी पानी के मामले में अति-अभाव से लेकर गंभीर अभाव वाली स्थिति में बताई जाती है। हर साल करीब दो लाख लोग साफ पानी तक पहुंच न होने से काल के गाल में समा रहे हैं।

कोई कह सकता है कि पानी के संकट को इस तरह से देखना या दिखाना अतिरंजित है। बेशक अभी हमें पानी की कमी से एकमुश्त हादसे की उतनी बुरी खबरें मिल नहीं रही हैं। दरअसल, यह हालत उतनी भयावह इसलिए नहीं दिख रही है कि हमने भूजल पर निर्भरता ज्यादा बढ़ा ली है। यह खतरे की तीसरी घंटी है। कई शोध बताते हैं कि इस समय हर साल बड़ी तेजी से भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है। सनद रहे कि भूजल असीमित नहीं है। नीति आयोग की 'वाटर कंपोजिट इंडेक्स' रिपोर्ट के मुताबिक भी भूजल खत्म हो रहा है। दूसरे देशों से अपनी तुलना करें तो दुनियाभर में जमीन से उलीचे जा रहे कुल भूजल का एक चौथाई हिस्सा सिर्फ भारत में निकाला जा रहा है। जबकि पूरी दुनिया को बारिश से जितना पानी मिलता है उसका सिर्फ चार फीसद हमारे हिस्से में आता है। सरकारी सर्वेक्षणों के मुताबिक सन 2020 तक 21 महानगरों में भूजल खत्म हो जाएगा। जल संकट सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है। देश के हाल फिलहाल के राजनीतिक माहौल में जल संचयन की क्षमता बढ़ाने, बांधों की मरम्मत, जलाशयों की गाद निकालने, भूजल संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे कम से कम चुनावी मुद्दों की सूची में तो आ ही जाने चाहिए थे। हम उस दौर में हैं जब जल संकट पर गंभीरता से सोचने का यह आखिरी मौका है।

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Rashtriya Sahara, Delhi
Thursday, 9th May 2019;

वायदे के अनुसार दिल्ली को जलापूर्ति करता रहे हरियाणा

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, 2014 के आदेश का पालन करे हरियाणा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली को हरियाणा से जल आपूर्ति के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को अगाह किया कि वह अपने वायदे के अनुसार दिल्ली को नियमित जलापूर्ति करता रहे और उसमें कोई कटौती नहीं करे। वह वर्ष 2014 के अदालती आदेश का पालन करे।

उसने इस बात पर नाराजगी जताई कि दिल्ली को मांग के अनुरूप जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली व हरियाणा सरकार के जल आपूर्ति से संबंधित विभागों को भी अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर मांग के अनुरूप जलापूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली आने पर जल के प्रवाह को टीला बनाकर रोके जाने के आरोप की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। उसने अवकाशप्राप्त न्यायमूर्ति इन्द्रमीत कौर कोचर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय कमेटी गठित कर उससे कहा है कि वह जांचकर बताए कि क्या जलापूर्ति रोकने के लिए विभिन्न जगह टीला बनाया गया है। टीला कितनी दूर पर है और उससे क्या जलापूर्ति बाधित हो रही है। दिल्ली को पानी की आपूर्ति में और कौन सी बाधाएं हैं। पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले दें। पीठ ने इसके साथ ही सुनवाई 20 मई के लिए स्थगित कर दी और कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे का दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कहा था कि उसने दिल्ली से दो सौ किमी की दूरी पर टीला बनाया है और उससे दिल्ली को जलापूर्ति में कोई बाधा नहीं आ रही है। इसको लेकर हरियाणा व पंजाब हाईकोर्ट में भी याचिका लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वह अपने वायदे के अनुसार रोजाना मुनक कैनाल से 719 क्यूसेक व और अन्य कैनाल के जरिए 330 क्यूसेक जल की आपूर्ति करता रहे। वह अपने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी पहले की तरह रोजाना पानी की आपूर्ति करे।

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019..... in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi) ✓
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

No relief till Friday, expect rain next wk

Overcast Sky Likely On Polling Day, Says IMD

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: It was a sweltering day in the capital on Wednesday with parts of the city crossing a maximum of 43 degrees Celsius. The Safdarjung station, taken as the base for the Delhi's weather, recorded a maximum temperature of 41.8 degrees Celsius — three notches above normal.

IMD, however, has forecast improvement over the next 72 hours with a thunderstorm likely to hit Delhi on Friday. Delhi could see gusty winds with dust storm and thunderstorm activity from Friday onwards, while the day of polling — Sunday — is likely to see overcast conditions and 'thundery' development, officials said.

Rain is, meanwhile, forecast for Tuesday, which could bring down the maximum temperature to around 36 degrees. "A western disturbance is affecting Delhi which could lead to an increase in moisture and thunderstorm activity. Wind speeds will pick up from Friday onwards and light rain could occur in isolated locations," said a senior met official.

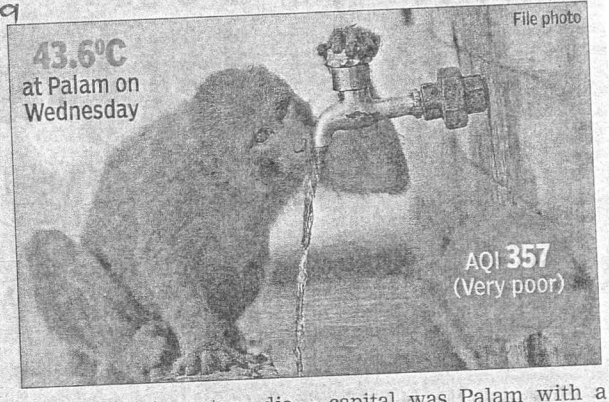

Delhi's minimum temperature on Wednesday was 23.6 degrees Celsius, while the hottest location in the capital was Palam with a high of 43.6 degrees. Palam had recorded the season's hottest day on April 30 when the mercury touched 45.3 degrees.

Delhi's air quality, meanwhile, deteriorated to 'very poor' with an AQI of 357. SAFAR says a dust storm across northern India is influencing Delhi's air quality and the AQI may turn 'severe' soon.

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 ... in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Locking CO_2 in a rock may check global warming

TD6-G

But Experts Need To Make Sure Gas Doesn't Migrate To Surface And Contaminate Drinking Water

Saint-Ursanne: Swiss scientists are injecting carbon dioxide into rock deep inside a mountain to discover if the gas leaks out or if it can be locked away to stop it contributing to climate change.

Inside Mont Terri in the Jura Mountains, a layer of impermeable clay could potentially trap carbon dioxide, the main greenhouse gas causing global warming.

At a laboratory deep inside the mountain, scientists have begun pumping carbon dioxide dissolved in salt water into the rock. They will see if the gas will interact with the clay and whether a fault-line will allow it to seep out.

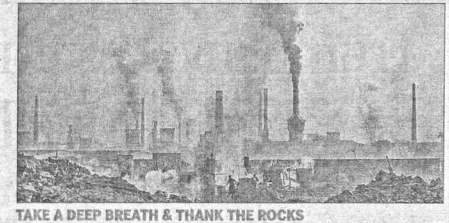

TAKE A DEEP BREATH & THANK THE ROCKS

The first eight-month phase of the experiment involves only 500mg of carbon dioxide pumped into the rock through a borehole. "If this rock has a fault in it, is it possible that the CO_2 comes up through the fault. This is what we want to answer," said Alba Zappone, a researcher at Zurich's ETH University.

Geological storage of CO_2 already exists, but existing sites are usually in uninhabited places, such as the Algerian desert or under the Norwegian North Sea, said Christophe Nussbaum, the Mont Terri project manager.

"What is new is that, if one day we want to stock CO_2 in Switzerland, which is a densely populated region, we need to make sure that the CO_2 won't migrate into the surface and contaminate, for instance, drinking water sources. This is one of the major stakes here," Nussbaum said.

Swiss citizens produce an average of about 5.8 tonnes of CO_2 annually, he said. The project is supported by Switzerland, France, Canada, Japan and the US, and energy firms.

But environmental organisations like Greenpeace are worried that the project's findings could turn into a "right to pollute" and detract from efforts to reduce emissions, which are driving a disastrous rise in global temperatures.

"What worries us is to see that the necessary efforts needed to limit greenhouse gas emissions are not being made," said Mathias Schlegel, Greenpeace spokesman. REUTERS

UK goes a week without burning coal

Britain has gone a week without burning coal for electricity for the first time since the 19th century. Power operator National Grid says coal hasn't contributed to the UK electricity mix since the afternoon of May 1. The landmark was reached two years after Britain had its first coal-free day since the Industrial Revolution. Fintan Slye, director of National Grid Electricity System Operator, said coal-free power would become the "new normal" as Britain generates more power from wind, solar and other renewable sources. The government says Britain will eliminate coal from its power supply by 2025. It has set a deadline of 2050 to eliminate greenhouse gas emissions altogether. AP

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi) ✓
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

HC tells Haryana to stick to its water commitment

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi high court on Wednesday secured water supply levels for the capital this summer, directing Haryana to ensure no disruptions or reductions occur in the water volumes and it sticks to the December 2014 commitment.

The court also strongly disapproved of Haryana's "conduct" where the neighbouring state pressured the Delhi government to withdraw an application from HC. In the plea Delhi government, through DJB, had urged the court to protect water supply for the state.

The jal board had alleged that in the Upper Yamuna River Board (UYRB) meeting of April 18, Haryana had asked DJB to first withdraw all cases on the water issue from the courts as a pre-condition for it to consider release of water to Delhi. A bench of Chief Justice Rajendra Menon and Justice A J Bhambhani noted Haryana's stand, adding that it is "reflected in the minutes of the meeting" and sought to know why it "asked for withdrawal of the plea".

As per the 2014 undertaking in HC, Haryana must release 719 cusecs of water per day into Munak canal and 330 cusecs per day in Delhi Sub Branch Canal. In addition, HC said that water being supplied to the Wazirabad treatment plant from Haryana, which caters to most of central Delhi including Lutyen's zone, should continue in the same quantities as was being done in the past.

The court is hearing a PIL by advocate S B Tripathi seeking sufficient water supply for Delhi.

Meanwhile, the bench took a grim view of allegations of sand mining and bunds being constructed along the Yamuna river bed and set up a high-level committee headed by retired justice Indermeet Kaur. The court said the retired judge along with amicus curiae senior advocate Rakesh Khanna will inspect if obstructions have been put in the canals carrying water meant for the Wazirabad plant as claimed by DJB through standing counsel Sumeet Pushkarna.

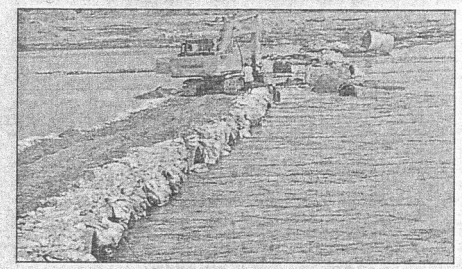

The high court has set up a high-level committee to look into the allegations of sand mining and bunds being constructed along the river bed

The court said the committee should submit its report before the next date of hearing on May 20, when it will take further action based on the panel's findings. High court's directions came on DJB's application informing the court that it is being coerced to withdraw all its earlier pleas for protecting water supply to the national capital.

However Haryana government maintained that the 'bunds' were 200km away from the Delhi-Haryana border and didn't interfere with water flow, but the bench refused to accept this argument, leaving it to the panel to examine "whether the bunds are 200 km or 20 metres away from the border" and would they "impact the supply of water to the national capital".

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi) ✓
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Gadkari rakes up river water flow to Pak. again

'Govt. making road map to stop water'

PRESS TRUST OF INDIA
AMRITSAR

Union Minister Nitin Gadkari on Wednesday warned Pakistan that India will not hesitate to stop water of rivers flowing to that country if Islamabad does not end its support to terrorism.

"The Union government is already making a road map to stop water of rivers flowing from India into Pakistan," he said at a campaign rally in Amritsar.

The Minister said that the government is planning to build six water dams in Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh and Rajasthan and this step would solve the water problem enormously.

"There was a water treaty between India and Pakistan in 1960 and its basis was peaceful relations, but if the present face of terrorism is not changed, in such circumstances, India wouldn't take much time to take the harsh decision of stopping river water to Pakistan," the BJP leader said.

Excess water

He said that the excess water will be given to Punjab and Haryana to address shortage in agriculture.

On river water distribution between Punjab and neighbouring Haryana, he said that the issue has to be sorted out without disturbing the water available to Punjab. Mr. Gadkari said that the Modi government did what was not done in the last five decades.

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times ✓
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Odisha death toll rises to 41

For power restoration additional skilled manpower was drawn from Bengal, Telangana & Andhra

PRESS TRUST OF INDIA
BHUBANESWAR, 8 MAY

The toll in cyclone Fani on Wednesday rose to 41, while power restoration work is on full wing in the affected areas with additional skilled manpower being drawn from other states, an official said.

The toll was 37 till Tuesday, the district collectors have confirmed four more deaths due to the cyclone which made a landfall in Puri on Friday, information and public relations secretary Sanjay Singh said without naming the districts from where fresh deaths were reported.

The official said restoration of water supply was the first priority of the state government after the cyclone and it has been achieved in both Bhubaneswar and most parts of Puri.

"We have engaged diesel generators in places for running the water pumps where electricity is not available," he said.

"We will be able to fully restore power supply in the state capital by 12 May," Singh said while briefing the media on the restoration works following the massive devastation due to the cyclone which ripped apart water supply, electricity and telecom infrastructure in over 11 coastal districts.

On the power restoration problem, he said work is on full swing with additional skilled manpower drawn from states like West Bengal, Telangana and Andhra Pradesh. "While 80 per cent of electricity consumers will get power by 10 May, the process will be completed by 12 May in Bhubaneswar," Singh said.

The power restoration work in Puri district is picking up and in the first phase of consumers will get electricity in Grand Road (Badadanda) area on 12 May, said Singh, who has been assigned the task of managing media and logistics in the post-cyclone period.

He, however, could not give any time line for full restoration of power supply in Puri district in the face of massive destruction of infrastructure in the worst cyclone hit areas.

"We have to rebuild the power infrastructure afresh in many places of Puri district which was slammed by high velocity wind at a speed of over 200 kmph," Singh said.

Cyclone *Fani* has damaged five 400 kv towers, 27 number of 220 kv towers, 21 number of 130 kv towers, four 220 kv grids, and four 132 kv grids in Puri.

Similarly, 5,030 km of 33 kv lines, 38,613 km of 11 kv line, 11,077 distribution transformers, and 79,485 km of low tension lines have been damaged in the calamity, the Special Relief Commissioner (SRC) said in its situation report.

The government has sought cooperation of the power consumers and said time is required to fully restore power connection in the cyclone devastated areas. As many as 1.56 lakh new electric poles have been uprooted in the 'extremely severe' cyclone *Fani*.

Rlys to resume normal services from Puri by 12 May

PRESS TURST OF INDIA
NEW DELHI, 8 MAY

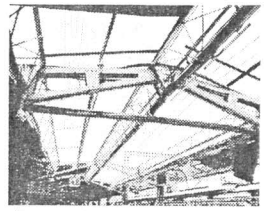

In an effort to resume connectivity with Odisha's Puri in the aftermath of the devastation wreaked by cyclone Fani, the Railways on Wednesday said it will start normal services from the tourist town by 12 May but the complete restoration of the severely damaged railway station can take up to three months.

Extremely severe cyclonic storm 'Fani' made landfall in the coastal town on 3 May, unleashing copious rain and windstorm with speeds of up to 175 kmph, and left behind a trail of destruction in 18 districts of Odisha and Andhra Pradesh.

The Railways had cancelled 595 trains since the cyclone hit the state on May 3 and has so far managed to restore 141 of them, including 34 trains originating from Bhubaneshwar.

"Today (Wednesday) we have restored three pairs of express trains from Puri and we will gradually increase the number. This decision has been taken by factoring in the repair work of the over-head wires, poles and the signalling system that needs to be done. By 12 May, we will resume normal services of trains from Puri. However, repair work of the Puri railway station and the Puri coach maintenance complex will take up to three months as these have been severely damaged," East Coast Railway (ECoR) chief spokesperson J P Mishra said. "Our nearby divisions and even the other zones have really cooperated and collaborated with us to ensure that we restore services quickly," Mishra said.

There are about 52 trains originating from Puri daily, of which 40 are express trains while 12 are passenger trains. The national transporter has also paid advance salary for the month of May to its staff of Puri and Khurda Road stations.

Central govt team to soon visit Odisha

NEW DELHI, 8 MAY

A team from the central government will soon visit Odisha to assess the damage caused by cyclone *Fani*.

Reviewing the relief measures in Odisha, cabinet secretary P K Sinha asked concerned officials of the state and the Centre to focus on implementation of the priority plans prepared for restoration of power and telecommunications in Puri and Bhubaneswar and monitor the progress on a day-to-day basis.

"On the request of Odisha, he further directed that a central team may visit Odisha soon to assess the extent of damage caused by cyclone Fani," a statement issued by the Home Ministry said.

The National Crisis Management Committee (NCMC), under the cabinet secretary, reviewed the rescue and relief measures in affected areas with the senior officials of the state government and central agencies concerned. The state government, in coordination with the Centre, has prepared a detailed plan identifying priority areas for restoration of power and telecom facilities in Puri and Bhubaneswar. PTI

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

Coming decade crucial for our planet's survival

9.S

BHARAT DOGRA

In recent years there has been a growing recognition that climate change is a problem that can seriously disrupt the life-nurturing conditions of planet earth. Earlier, scientists had reached broad agreement that it is necessary to restrict global warming to 2 deg. C above pre-industrial levels. But then it was realised that even this could have catastrophic consequences. Hence there has been increasing consensus in the scientific community about the need to restrict global warming to a level of 1.5 deg. C above pre-industrial levels.

As an increase of 1 deg. C has already taken place, this leaves us very little room but again the scientific community is clear that it is still within the realm of science (and human effort) to achieve this if there is a very firm global commitment.

It is very important for humanity to make this commitment because otherwise the catastrophic impacts of climate change will be unacceptably high. Restricting global warming to this level calls for immediate and far-reaching changes not just in energy, industry and transport systems but also even wider changes in economy, living patterns, social and political mobilisation.

In October 2018, a widely cited and discussed report of the most important scientific body on climate change (the Inter-governmental Panel on Climate Change or the IPCC) warned that there are only a dozen years for global warming to be kept to the limit of 1.5 deg. C. Debra Roberts, co-chair of the working group on impacts, said this was the largest clarion call from the scientific community. This report tells humanity that this is the moment and we must act now, Roberts said.

If we succeed in restricting climate change to 1.5 deg. C it will be a very significant achievement, but it will not mean there will be no significant adverse impacts of climate change at this level. A range of serious adverse impacts are being experienced even now at 1 deg. C above pre-industrial levels. Significant adverse impacts will certainly be there at 1.5 deg. C above pre-industrial levels. But we will hopefully be able to keep these within tolerable limits.

James Hansen, the former NASA scientist who played an important role in drawing attention to climate change, has said that both 1.5 deg. C and 2 deg. C would take humanity into uncharted and dangerous territory as they are both well above the Holocene era range in which human civilization developed but there is a big difference . He said, "1.5 gives young people and the next generation a fighting chance of getting back to the Holocene or close to it."

Will humanity seize this chance for the young generation and generations to come? To make this a possibility, as the IPCC report mentioned, the window of opportunity available to us will remain open only up to around year 2030 or so. In other words, the decade 2020-30 is going to be the most important for saving the life-nurturing conditions of planet earth.

While discussion is more in the context of climate change there are several other serious environmental problems which are also reaching a critical stage around the same time. These problems may also impact the crisis of climate change in several ways, aggravating it and adding to it, while at the same time these may also be worsened further by climate change impacts.

These problems include scarcity and pollution of freshwater, air pollution, pollution and disruption of ocean life systems, species extinction and habitat loss, rapid decline of bio-diversity and food production systems, serious risks from proliferation of dangerous chemicals and radiation. The fact that so many people and children in the world still suffer from poverty, hunger, malnutrition and other deprivations increases the adverse impact of these serious environmental problems in several ways.

At the same time the risks posed by weapons of mass destruction are also increasing. UN Secretary General Antonio Guterras said some time back that global anxieties regarding nuclear weapons are at their highest levels since the end of the cold war. A little before this former Soviet President Mikhail Gorbachev said, "The worst thing that has happened in recent years is the collapse of trust in relationships between major powers. The window to a nuclear-free world…is being shut and sealed right before our eyes."

We may add that since these statements were made the situation has deteriorated because of the failure to renew a crucial treaty to reduce nuclear weapon risks and the increasing doubts being expressed that another critical treaty due for renewal in 2021 may not be renewed. This is as far as the treaties concerning nuclear weapons of the USA and Russia are concerned.

However, there are also serious concerns regarding growing tensions and nuclear weapon risks in other countries possessing nuclear weapons, perhaps most notably the increasing tensions between India and Pakistan.

Hence the coming years are going to be critical from the point of view of efforts for decreasing nuclear weapon risks. In addition the future risks from robot weapons are extremely high. As the world is now in the early stages of development of robot weapons, the next few years will be crucial from the point of view of any major initiatives to reduce the growing and unpredictably high risks from robot or AI weapons.

Hence it is clear that a number of serious problems appear to be converging around the same time leading to an unprecedented human-made survival crisis on planet earth. Urgent steps need to be taken to resolve this crisis without further delay and the next decade will be the most crucial from this perspective. There are very compelling reasons to declare the next decade as the Decade for Saving Earth as this will help to focus attention on the most important challenges ahead of us. This is a campaign that I have taken up with a lot of hope and if some of the readers of the book I have written also join such efforts then my efforts will be amply rewarded.

The writer is a freelance journalist who has been involved with several social movements and initiatives. His book Planet in Peril, Survival Crisis - People's response the Only Way Forward has just been published by Vitasta, Delhi.

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi) ✓
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

आतंकवाद पर रोक नहीं लगाई तो रोक देंगे पाकिस्तान का पानी

अमृतसर, (वार्ता): केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि अगर पाकिस्तान ने आंतकवाद पर रोक नहीं लगाई तो भारत पाकिस्तान को जा रहे नदियों के पानी पर रोक लगा सकता है।

श्री गडकरी ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि 1960 में हुई जल संधि के अनुसार भारत की छह में से तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया था। उन्होंने कहा कि संधि में लिखा गया है कि आपसी प्रेम और भाईचारे के चलते नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आंतकवाद पर अंकुश नहीं लगाता तो भारत सरकार पाकिस्तान को जा रहे नदियों के पानी पर रोक लगा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि केन्द्र सरकार की देश की सभी दरियाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने की योजना है जिससे देश के सभी राज्यों की पानी की समस्या सुलझाई जा सकेगी। Pg-9

छह राज्यों में किया जा रहा है बांध का निर्माण... उन्होंने कहा कि छह राज्यों में बांध का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से शाहपुर कंडी का बांध तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि 26 हजार एकड़ में बने शाहपुर कंडी बांध का पानी पंजाब और हरियाणा को दिया जाएगा। यहां 206 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। पंजाब में पटियाला फीडर से जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर के किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पांच वर्षों दौरान किये गये विकास कार्यों की चर्चा करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश में चार और छह मार्ग की सड़कों का बढ़िया निर्माण करवा कर देश में एक क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है जिसके पूरा होने पर दिल्ली से कटरा की दूरी कम होकर 572 किलोमीटर रह जाएगी। इसी प्रकार दिल्ली से अमृतसर की दूरी केवल चार घंटे में तय की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि गुड़गांव से मुम्बई तक बनाये जा रहे हाई-वे से दिल्ली से मुम्बई का सफर 12 घंटे में तय किया जा सकेगा।

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi)

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

यमुना पर बांध !, हाई कोर्ट ने जांच के लिए बनाई कमिटी

कोर्ट ने हरियाणा के बर्ताव को बताया गलत, लगाई फटकार

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

यमुना में पानी की सप्लाई को लेकर हरियाणा को दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को डांट पड़ी। कोर्ट ने हरियाणा को उसके बर्ताव के लिए फटकार लगाई। वहीं, अवैध बांध के निर्माण की जांच के लिए एक कमिटी गठित की है। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि 18 अप्रैल को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में हरियाणा ने उससे कहा था कि वह पानी के मुद्दे पर दर्ज सभी मामले कोर्ट से वापस ले, तभी वह दिल्ली को पानी देने पर विचार करेगा। दिल्ली सरकार का यह भी आरोप है कि पानी की सप्लाई में रुकावट के इरादे से यमुना पर अवैध बांध का निर्माण किया जा रहा है।

इस पर चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस ए जे भंभानी की बेंच ने हरियाणा से कहा कि उसका बर्ताव मीटिंग की डिटेल्स में झलक रहा है। हरियाणा ने दिल्ली से अर्जी वापस लेने को क्यों कहा? बेंच ने कहा कि हरियाणा ने दिसंबर, 2014 में कोर्ट में दिल्ली को जितना पानी देने का वादा किया था, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आदेशों के मुताबिक, हरियाणा को रोज मुनक नहर में 719 क्यूसेक पानी और दिल्ली उप शाखा नहर में 330 क्यूसेक पानी छोड़ना है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को दिए जा रहे पानी की मात्रा इतनी ही रहनी चाहिए। इसी प्लांट से लुटियन जोन और सेंट्रल दिल्ली में पानी सप्लाई होता है। यमुना पर बनाए गए बांध की जांच के लिए कोर्ट ने एक कमिटी भी बनाई है। कोर्ट की रिटायर्ड जज इंद्रमीत कौर इसकी अध्यक्ष हैं। कमिटी को जांचना है कि क्या वाकई हरियाणा से जिन नहरों के जरिए दिल्ली के वजीराबाद प्लांट तक पानी की सप्लाई होती है, उस पर कोई पुश्ता बनाया गया है या नहीं। ऐसा दिल्ली जल बोर्ड दावा कर रहा है। कमिटी को 20 मई तक रिपोर्ट देनी है।

जल बोर्ड का दावा

दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि मई-जून में दिल्ली में गंभीर जलसंकट होता है। अगर हरियाणा 1133 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ता है तो दिल्ली में गंभीर जल संकट हो जाएगा। जल बोर्ड ने डीडी-8 नहर पर बने बांध की तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखीं। इससे वजीराबाद प्लांट तक पानी पहुंचता है। बेंच ने कहा कि कमिटी देखेगी कि पुश्ता दिल्ली की सीमा से 200 किमी. या 20 मीटर की दूरी पर है। उससे दिल्ली में पानी की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

News item/letter/article/editorial Published on 09.05.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Time of India (New Delhi)
Indian Express
Tribune

Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu (New Delhi)
Rajasthan Patrika (Hindi) ✓

Deccan Chronicle
Deccan Herald
The Times of India (A)
Business standard
The Economic Times

and documented at Bhagirath (English) & Publicity Section, CWC

तमिलनाडु के खिलाफ किसानों का धरना

कर्नाटक को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार: रमेश कुमार

कोलार. तमिलनाडु की ओर से मार्कण्डयय्या जलाशय परियोजना और केसी वैली परियोजना का विरोध जताने पर जिले के किसानों ने आक्रोश जताया और धरना दिया। इस दौरान तमिलनाडु का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। विधानसभा के अध्यक्ष केआर रमेश कुमार, विधायक के. श्रीनिवास गौड़ा के अलावा जिले के कई जनप्रतिनिधियों ने धरने में भाग लिया। इस अवसर पर रमेशकुमार ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार प्रदेश के हर विषय में हस्तक्षेप कर रही है। प्रदेश को अपने पानी का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। तमिलनाडु ने मैकेदाटू परियोजना के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई है। अब पेन्नार नदी के अंतर्गत पानी का इस्तेमाल करने की परियोजना का भी विरोध किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के बीच पेन्नार और पालार नदी के पानी के बंटवारे का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। कर्नाटक ने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने के लिए मालूर के पास मार्कण्डय्या जलाशय निर्मित करने की तैयार की है। इसके अलावा कोलार, चिकबल्लापुर, बेंगलूरु शहर और बेंगलूरु ग्रामीण जिले के 191 तालाबों को भरने के लिए केसी वैली (कोरमंगला और चलघट्टा वैली) परियोजना समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का पड़ोसी राज्य द्वरा विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडू ने आरोप लगाया है कि पेन्नार नदी के अंतर्गत पेयजल की कुछ परियोजनाओं और केसी वैली परियोजना से कावेरी नदी के नैसर्गिक बहाव प्रभावित होगा। तमिलनाडु ने कोलार जिले के मालूर के पास 240 करोड़ रुपए की लागात से निर्मित होने वाले जलाशय से उसके छह जिलों को पानी रोकने का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया है। तमिलनाडु ने दावा किया है कि इस परियोजना के लिए उसकी सहमति जरूरी है। कावेरी नदी के जल बंटवारे के विषय को लेकर 16 फरवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय के आदेश का उलंलघन करने का आरोप लगाया है।